# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 23 | 1-15 दिसंबर 2023 | ₹ 20/-

# विधानसभा चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत उर्दू अखबारों की नजर में

- उत्तर प्रदेश के 108 मदरसों को 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग
- डेनमार्क में क़ुरान के अपमान के खिलाफ कानून पारित
- रूस द्वारा अरब जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास
- आईएसआईएस की भारत पर हमले की साजिश

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

## राष्ट्रीय

विधानसभा चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत उर्दू अखबारों की नजर में 04
उत्तर प्रदेश के 108 मदरसों को 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग 09
आईएसआईएस की भारत पर हमले की साजिश 11
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने का फैसला 12
तेलंगाना के भाजपा विधायकों का अकबरुद्दीन ओवैसी से शपथ लेने से इंकार 14

## विश्व

डेनमार्क में कुरान के अपमान के खिलाफ कानून पारित 15
गाजा में युद्धविराम के प्रयासों की विफलता पर संयुक्त राष्ट्र बेबस 16
पाकिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि 18
बांग्लादेश के विपक्षी दलों द्वारा चुनाव का बहिष्कार 19
फ्रांस के सबसे बड़े इस्लामी स्कूल का सरकारी अनुदान बंद 20

## पश्चिम एशिया

रूस द्वारा अरब जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास 21
सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले 23
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की जेल में भूख हड़ताल 24
सऊदी अरब द्वारा भारतीयों के लिए उमरा को आसान बनाने की घोषणा 25
सऊदी अरब में पूंजी निवेश करने वाली कंपनियों को करों में 30 वर्ष की छूट 26

# सारांश

उर्दू के अखबारों ने अपने संपादकीय में स्पष्ट रूप से कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। इन अखबारों का यह भी कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हैट्रिक लगाने के बारे में अब कोई संदेह नहीं रहा है। भाजपा ने जो चुनावी रणनीति अपनाई थी वह कारगर साबित हुई है। यह प्रधानमंत्री मोदी का ही कमाल है कि उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नेतृत्व ऐसे लोगों को सौंपा है, जो बिल्कुल नए चेहरे हैं। पार्टी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने का जो प्रयोग किया था वह सफल रहा है। इसके साथ ही पार्टी अपने आंतरिक मतभेदों पर नियंत्रण करने में भी सफल रही है।

उर्दू अखबारों का कहना है कि विधानसभा के इन चुनावों में कांग्रेस की हार उसकी गलतियों और अति आत्मविश्वास के कारण हुई है। मोदी लहर का सामना करने के लिए राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' का जो अभियान शुरू किया था वह प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता के सामने टिक नहीं पाया। वहीं, पार्टी की आंतरिक गुटबाजी का प्रभाव भी इन चुनाव परिणामों पर पड़ा है। भाजपा का सामना करने के लिए कांग्रेस ने इंडिया नामक जो गठबंधन बनाने का प्रयास किया था उसकी पहली ही परीक्षा में हवा निकल गई है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों की उपेक्षा की, जो उसे काफी महंगी पड़ी। इन चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ है उससे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की जांच के लिए एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में जो विशेष जांच दल का गठन किया था उसकी प्रारंभिक जांच में अनेक सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 108 मदरसों को केवल दो साल में विदेशी स्रोतों से 150 करोड़ की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सवाल यह पैदा होता है कि कहीं इस विदेशी धनराशि का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के लिए तो नहीं किया जा रहा था? इसी संभावना को समक्ष रखते हुए राज्य सरकार ने इस बात की गहन जांच करवाने का फैसला किया है कि जिन मदरसों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी उन्होंने इस धनराशि का उपयोग कहां-कहां किया है? इस संबंध में इन मदरसों के प्रबंधकों से खर्च का ब्यौरा मांगा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस्लामी मदरसों की संख्या में अचानक भारी वृद्धि हुई है। जबकि वहां पर इस्लाम के अनुयायियों की संख्या अधिक नहीं है। राज्य सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में भी सघन जांच कराने का निर्णय किया है और इस महीने के अंत तक संबंधित अधिकारियों से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आपसी मतभेदों के बावजूद मुस्लिम देश पैगंबर, कुरान और इस्लाम के नाम पर एकजुट हो जाते हैं और वे राजनीतिक दबाव बनाने में पूरी तरह से सक्षम भी हैं। इन इस्लामी देशों के दबाव के कारण हाल ही में डेनमार्क सरकार को कुरान और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अपमान की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष कानून संसद से पारित करवाना पड़ा है। इस नए कानून में कुरान, इस्लाम और रसूल का अपमान करने वालों के लिए दो साल की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

रूस ने मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने का विशेष अभियान छेड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि मध्य पूर्व के कुछ देशों की रहस्यमयी यात्रा की है। सैन्य, रक्षा और पेट्रोलियम उत्पादों के विकास के क्षेत्र में ईरान और रूस के बीच आपसी सहयोग बढ़ने से अमेरिका काफी परेशान है।

# विधानसभा चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत उर्दू अखबारों की नजर में

राज्य विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अधिकांश उर्दू अखबारों के स्वर में भारी बदलाव आया है।

**अवधनामा** (4 दिसंबर) के मुख्य समाचार का शीर्षक है, 'एग्जिट पोल की सारी भविष्यवाणियां गलत'। 'हिन्दी बेल्ट में फिर खिला कमल'। 'तेलंगाना में कांग्रेस ने लहराया परचम'। 'भाजपा ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को दिया जोरदार झटका'। 'मध्य प्रदेश में भी चला मोदी का जादू'। इसके साथ ही समाचारपत्र ने एक बॉक्स में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बयान भी प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'तीन राज्यों में भाजपा की जीत 2024 में हैट्रिक की गारंटी'।

हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले **सियासत** (4 दिसंबर) का शीर्षक है, 'दक्षिण भारत भाजपा मुक्त'। 'उत्तर भारत में भाजपा की जीत'। 'मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार'। 'तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी'। इसके साथ ही समाचारपत्र ने एक बॉक्स में समाचार प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'इन चुनाव परिणामों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा : विपक्ष का दावा'।

**इंकलाब** (4 दिसंबर) का शीर्षक है, 'मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत'। 'तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी'। 'एग्जिट पोल के सभी दावे धराशायी'। 'आज की हैट्रिक ने 2024 में हैट्रिक की गारंटी दे दी है : प्रधानमंत्री'। जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि तीनों राज्यों में कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय से वापसी करेंगे। समाचारपत्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान भी मुख्य पृष्ठ पर बॉक्स में प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'यह वैचारिक संघर्ष जारी रहेगा'।

**रोजनामा सहारा** (4 दिसंबर) का शीर्षक है, 'फिर चला मोदी मैजिक'। 'कांग्रेस के वायदे

बेअसर'। 'तेलंगाना ने दिया कांग्रेस को सहारा'। समाचारपत्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान बॉक्स में प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'जनता के दिलों में सिर्फ मोदी जी'। जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता को मोदीजी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (6 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'उत्तर भारत के तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे आश्चर्यजनक और निराशाजनक'। समाचारपत्र ने कहा है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, जिससे लोगों को लाभ भी पहुंचा था। सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप भी नहीं था, मगर इसके बावजूद अधिकांश मंत्रियों की शर्मनाक हार की वजह समझ से परे है। कहा जाता है कि खुद जीतने वालों को भी ऐसी जीत की आशा नहीं थी। अब ऐसा समझा जाए कि जनता की नजर में कल्याणकारी योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहा है। हैरानी की बात यह है कि गहलोत सरकार ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की तुष्टिकरण के लिए भी अनेक कदम उठाए थे, जिनमें गाय के गोबर को खरीदना भी शामिल था। गोशालाओं के बजट में भी भारी वृद्धि की गई थी, मगर इसके बावजूद जनता ने एक साफ-सुथरी सरकार को शर्मनाक हार का तोहफा देकर विदा कर दिया। मध्य प्रदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। अनैतिक गठजोड़ से बनी शिवराज सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, मगर नतीजे उम्मीदों के विपरीत निकले हैं। तीसरे प्रदेश छत्तीसगढ़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। इन चुनावी नतीजों ने न केवल हिन्दी पट्टी, बल्कि पूरे देश पर आक्रामक राष्ट्रवाद की पकड़ को और मजबूत कर दिया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि इन चुनाव परिणामों का लोकसभा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मानने का मेरे पास कोई मजबूत आधार नहीं है। समाचारपत्र ने मुसलमानों द्वारा कांग्रेस को वोट देने की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा है कि हालांकि मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, मगर कांग्रेस हाईकमान हमेशा मुसलमानों के जमीनी नेताओं को नजरअंदाज करती आ रही है।

**तासीर** (11 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'अगली बार 400 पार'। समाचारपत्र का कहना है कि तीन राज्यों के चुनावों में जबर्दस्त जीत के बाद भाजपा ने एक नया चुनावी नारा गढ़ा है और वह यह है कि अगली बार 400 पार। भाजपा के नेताओं को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की हवा निकली है उसका लाभ पार्टी को हिन्दी भाषी अन्य राज्यों में भी मिल सकता है। जिन तीन राज्यों में भाजपा ने जीत का झंडा लहराया है वहां पर लोकसभा की 65 सीटें हैं, जिनमें से अभी 61 सीटें भाजपा के पास हैं। हिन्दी भाषी राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में

लोकसभा की 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 170 सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह इन राज्यों में न केवल अपनी सीटें बरकरार रखे, बल्कि इनकी संख्या में और भी वृद्धि करे। हालांकि, भाजपा के लिए देश के 11 राज्यों में अपनी सीटों में बढ़ोतरी कर पाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करें तो भाजपा सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं, 400 सीटें प्राप्त करने के लिए पार्टी को असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 2019 की अपनी क्षमता को दोहराना होगा। अब तक भाजपा लोकसभा के चुनावों में नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरती रही है और इसके कारण उसे दोनों बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। हालांकि, मोदी लहर के बावजूद कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर भाजपा का अभी खाता भी नहीं खुला है।

**उर्दू टाइम्स** (4 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'दबा कमल का बटन लगी कांग्रेस को फांसी'। समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में चुनावी नतीजों पर आश्चर्य व्यक्त किया है और कांग्रेस के इस आरोप का समर्थन किया है कि भाजपा के पक्ष में चुनावी नतीजे ईवीएम मशीनों के कारण आए हैं। समाचारपत्र ने यह तर्क दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन राज्यों में सभी चुनावी विश्लेषक भाजपा की पतली हालत और कांग्रेस के पक्ष में लहर के दावे कर रहे थे वहां पर भाजपा एकतरफा कैसे जीत गई? समाचारपत्र ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का जिम्मेवार कमलनाथ को बताया है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकीं। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने गढ़ तेलंगाना में सिर्फ सात सीटें ही जीत सकी है। भाजपा हाईकमान ने अपने चुनावी सभाओं में कहा था कि कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस को फांसी लगाओ। जनता ने भी वैसा ही किया है।

**हमारा समाज** (5 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में विधानसभा के चुनावों में भाजपा की जीत को मोदी की लोकप्रियता की जीत बताया है और कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार को दोषी ठहराया है। इंडिया गठबंधन के एक मुख्य चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के बारे में यह टिप्पणी की थी कि उसने इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज कर दिया है और समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों को विधानसभा के चुनावों में महत्त्व नहीं दिया है। अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पांच सीटें दे देती तो उसे 10-12 सीटों पर हाथ न धोना पड़ता। अब भी समय है कि कांग्रेस जमीनी सच्चाई को देखते हुए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे।

**इत्तेमाद** (4 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आम चुनावों से केवल कुछ महीने पहले हुए विधानसभा के इन चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि जनता का रूझान क्या है। ये चुनावी नतीजे भाजपा के लिए संतोषजनक हैं। जबकि कांग्रेस के लिए चिंताजनक। कांग्रेस ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था। इन चुनावों में यह गठबंधन कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस ने इस गठबंधन के दलों को महत्व ही नहीं दिया। समाचारपत्र ने कहा है कि तेलंगाना में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सात सीटों पर कामयाबी से यह साफ है कि अल्पसंख्यकों का भरोसा आज भी असदुद्दीन ओवैसी पर है।

**अवधनामा** (13 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में इन चुनावों में भाजपा की जीत को मोदी की जीत बताया है। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि विधानसभा चुनावों में सफाया होने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने जमीनी सच्चाई का सामना करने के बजाय ईवीएम मशीन

में हेरफेर का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। समाचारपत्र का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा और जनता ने इसे स्वीकार किया। अब कांग्रेस सिर्फ तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना तक ही सीमित होकर रह गई है और उत्तर भारत से पूरी तरह से गायब हो गई है। मोदी सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि देश की जनता और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में यह विश्वास जागृत हो कि वे भाजपा के राज्य में सुरक्षित हैं।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (4 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि इन चुनावों में कांग्रेस हाथ मलती रह गई और भाजपा ने उससे दो राज्य छीन लिए हैं। ये चुनाव इसलिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण थे, क्योंकि इन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। राजनीतिक पंडितों का यह दावा था कि इन चुनावों में जिस भी पार्टी को सफलता मिलेगी वही लोकसभा का चुनाव जीतेगी। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि भाजपा के जीत का एक बड़ा कारण यह है कि उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ प्रयोग किए। पार्टी द्वारा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का प्रयोग सफल रहा। भाजपा ने आंतरिक मतभेदों को दूर करने का भी खास प्रयास किया, मगर कांग्रेस गुटबाजी पर नियंत्रण करने में विफल रही और इसका नतीजा उसे चुनावों में भुगतना पड़ा।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (5 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में विधानसभा के चुनावी नतीजों को चौकाने वाला बताया है, लेकिन इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में सत्ता प्राप्त करके दक्षिण भारत में भाजपा के प्रवेश के एक और प्रयास को विफल कर दिया है। ये चुनाव परिणाम निश्चित रूप से लोकसभा के आने वाले चुनाव को प्रभावित करेंगे। राजस्थान में जिस तरह से गहलोत सरकार ने अखबारों को अंधाधुंध विज्ञापन बांटे उससे साफ हो गया है कि अखबारों में विज्ञापनों के दम पर जनता के मत प्राप्त नहीं किए जा सकते और न ही चुनाव जीते जा सकते हैं। इसके लिए नेतृत्व की साख भी होनी चाहिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी झगड़े कांग्रेस को ले डूबे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजनस्थान में कांग्रेस के नेता अपने 'हैंगओवर' में डूबे रहे। इन चुनावों से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मामले को भी भुनाने का प्रयास किया था। पार्टी ने ओबीसी का जो खेल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में खेला था वह भी विफल रहा। जहां तक मुस्लिम विधायकों का संबंध है, विधानसभा के इन चुनावों में केवल 13 मुस्लिम विधायक ही जीत पाए हैं। मध्य प्रदेश में दो, राजस्थान में पांच और तेलंगाना में छह मुसलमान चुनाव जीतने में सफल रहे हैं।

**अवधनामा** (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में इन चुनावों में भाजपा की जीत को मोदी का जादू करार दिया है और कहा है कि यह सच्चाई है कि राहुल गांधी उत्तर भारत की जनता को प्रभावित करने में नरेन्द्र मोदी से पिछड़ गए। इसके साथ ही एग्जिट पोल के सारे दावे भी धराशायी हो गए।

**सियासत** (8 दिसंरब) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से तीन राज्यों में भाजपा की भारी जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे निराशाजनक रहे हैं, लेकिन अगर इनका विश्लेषण किया जाए तो वोटों के लिहाज से कांग्रेस और भाजपा में बहुत अंतर नजर नहीं आता है। हालांकि, भाजपा की यह जीत बड़ी जीत है और चुनावी नतीजों में वोटों के मुकाबले जीती गई सीटों का ही महत्व होता है। कर्नाटक में भाजपा की हार और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के जो हौसले गिरे थे, उनमें अब नया जीवन आया है और इसका असर आने वाले लोकसभा के चुनावों में पड़ेगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (13 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का पत्ता साफ करने के भाजपा के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव और राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा को सौंपकर यह संदेश दे दिया है कि अब राजस्थान से वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का युग समाप्त हो गया है। वसुंधरा दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनीं और शिवराज सिंह चौहान ने चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित किया। केंद्र को इन दोनों का ताकतवर होना पसंद नहीं आया और चुनाव में उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात लॉबी पूरे देश में शतरंज के अपने मोहरों को सत्ता में लाना चाहती है। समाचारपत्र ने यह संदेह व्यक्त किया है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी यही खेल खेला जा सकता है।

**रोजनामा सहारा** (4 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों को भी इन चुनावों में भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान के नतीजे परंपरा के अनुसार आए हैं, क्योंकि वहां पर हर पांच साल के बाद नए पार्टी को सत्ता में लाया जाता है। समाचारपत्र ने छत्तीसगढ़ के नतीजों पर हैरानी प्रकट की है, जहां पर अप्रत्याशित रूप से भूपेश बघेल को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है और भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस की आत्ममुग्धता और अति आत्मविश्वास के चलते उसे तीन राज्यों में शर्मनाक हार झेलना पड़ा है। जबकि भाजपा ने कांग्रेस के आतंरिक विवादों का भरपूर लाभ उठाया और चुनाव अभियान को बड़े कारगर ढंग से चलाया। हालांकि, इन राज्यों में भाजपा की सफलता का श्रेय नरेन्द्र मोदी की छवि को देने से इंकार करना सरासर गलत होगा। वर्तमान नतीजों से लोकसभा के आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को फायदा होगा। इन चुनाव परिणामों को देखते हुए विपक्ष को नई रणनीति बनाने पर विचार करना होगा।

**इंकलाब** (5 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और इस बात पर भी

सोचना होगा कि आखिर क्या बात है कि वह अधिकतर चुनाव जीतते जीतते हार जाती है और भाजपा हारते हारते जीत जाती है। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत बताई जाती थी, मगर पार्टी सिर्फ एक ही राज्य में जीत पाई। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस में काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता मौजूद हैं, मगर वे कोई करिश्मा नहीं कर पाते। हालांकि, यह सच है कि दस साल सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, मगर इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की हार का एक मुख्य कारण उसके कारगर संगठनात्मक ढांचे का न होना है। इन चुनावों में हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया है।

**अवधनामा** (4 दिसंबर) के अनुसार विधानसभा चुनाव के नतीजों से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए इंडिया नामक जो गठबंधन बनाया था वह पहली ही परीक्षा में विफल हो गया है। हकीकत यह है कि राज्य विधानसभा के इन चुनावों में इंडिया गठबंधन आंतरिक विवादों का शिकार रहा और इसके नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। मोदी लहर का सामना करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस इससे मजबूत होगी, मगर इन चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि मोदी के जादू के कारण उनका यह प्रयास पूरी तरह से विफल रहा है।

## उत्तर प्रदेश के 108 मदरसों को 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग

**मुंबई उर्दू न्यूज** (8 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों की जांच के लिए जो एसआईटी का गठन किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले दो सालों में उत्तर प्रदेश के 108 मदरसों को 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि मदरसों को खाड़ी देशों से धन की प्राप्ति होती रही है। अब जांच टीम इस मामले को गहराई से खंगालने पर विशेष ध्यान दे रही है। जांच रिपोर्ट के अनुसार जिन मदरसों को विदेशी फंडिंग होती रही है वे बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, देवबंद और आजमगढ़ सहित कई अन्य जिलों में स्थित हैं। अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने मदरसों के प्रबंधकों से इस बात की विस्तृत जानकारी मांगी है कि उन्हें यह धनराशि विदेशों से किस संगठन द्वारा किस माध्यम और खाते से भेजी गई थी और बाद में इस विदेशी धनराशि को मदरसों के प्रबंधकों ने कैसे खर्च किया? इस संबंध में रसीदें और बिल आदि

भी मांगी गई हैं, ताकि जांच एजेंसी इस बात का पर्दाफाश कर सके कि इस बड़ी धनराशि को विदेशों से किस लक्ष्य हेतु भेजा गया है।

गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में इस जांच दल का गठन किया था और यह जांच दल राज्य के 84 हजार मदरसों की जांच कर रहा है। इनमें से केवल 16500 मदरसे ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। मोहित अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार ने जांच पूरी करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की है। जांच दल ने मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की है। गुप्तचर सूत्रों का दावा है कि विदेशों से लगने वाली उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मदरसों की संख्या में अचानक से भारी वृद्धि हुई है।

**रोजनामा सहारा** (7 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। सरकार ने 4394 मदरसों की जांच करवाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 560 मदरसों से होगी। इस जांच के लिए अल्पसंख्यक विभाग ने एक समिति का गठन किया है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और मंडलीय उपनिदेशकों को यह निर्देश दिया है कि वे 30 दिसंबर तक मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। यह जांच मदरसों की मान्यता के लिए दिए गए प्रमाणपत्र में दी गई सूचनाएं, उसकी वर्तमान स्थिति, मदरसों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनके पाठ्यक्रम के संबंध में होगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि मदरसों की बार-बार जांच करने से उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा पड़ती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश में 25 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। मदरसों के प्रबंधकों का आरोप है कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से वह किसी न किसी बहाने मदरसों की जांच करवा रही है और

हर साल इस संबंध में एक नया आदेश जारी कर दिया जाता है।

**इंकलाब** (9 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा कम संख्या में फॉर्म भरे जाने पर बोर्ड के रजिस्ट्रार ने चिंता प्रकट की है और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जिन मदरसों में कम छात्र हैं, उनके बारे में विशेष रिपोर्ट दी जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर मदरसों का सरकारी अनुदान रोका जा सकता है और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। पिछले सालों के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद यह बात प्रकाश में आई है कि सेकेंडरी परीक्षाओं जैसे मुंशी और मौलवी की परीक्षाओं के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त मदरसे भी परीक्षार्थियों से फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, जो मदरसों की मान्यता का एक अनिवार्य हिस्सा है। बोर्ड की रजिस्ट्रार डॉ. प्रियंका अवस्थी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अरबी और फारसी मदरसों के लिए मौलवी और मुंशी के स्तर तक की मान्यता की यह अनिवार्य शर्त है कि उनमें कम-से-कम 150 छात्र हों। इनमें से मुंशी और मौलवी की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 30 से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि संबंधित मदरसे या तो काम नहीं कर रहे हैं या उनमें छात्रों की संख्या निर्धारित संख्या से बहुत कम है।

## आईएसआईएस की भारत पर हमले की साजिश

**उर्दू टाइम्स** (10 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा देश भर में हमले करने की साजिश का पता लगाया है। इस साजिश से जुड़े हुए आरोपियों की तलाश में कर्नाटक और महाराष्ट्र के 44 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। कर्नाटक में एक, पुणे में दो, ठाणे रूरल में 31, ठाणे सिटी में 9 और भायंदर में एक स्थान पर छापा मारा गया है। एनआईए अब तक इस खूनी आतंकी संगठन से जुड़े हुए 13 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इन आरोपियों ने देश भर में आतंकवाद और हिंसा फैलाने की योजना बनाई थी। इससे पहले एनआईए जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में छापे मारकर

कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त कश्मीर घाटी में बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, पुलवामा आदि जिलों में भी छापे मारे गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि विदेशों के इशारे पर यह गिरोह भारी पैमाने पर जाली नोट छाप रहा था। एनआईए ने छापे के दौरान छपी हुई जाली करेंसी, नोट छापने के पेपर और डिजिटल संयंत्र जब्त किए हैं। इस गिरोह के तार सीमा पार से जुड़े पाए गए हैं।

**इंकलाब** (10 दिसंबर) के अनुसार एनआईए ने भिवंडी, पड़घा, मीरा रोड़, पुणे और बेंगलुरु में भी छापे मारकर 15 अन्य मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इस मॉड्यूल का प्रमुख महाराष्ट्र का रहने वाला साकिब नाचन है। एनआईए का दावा है कि इस आतंकी मॉड्यूल के तार देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए हैं। अधिकांश छापे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मारे गए हैं। जिन मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया है उनमें साकिब नाचन, हासिब मुल्ला, मुसाब मुल्ला, रेहान सुसे, फरहान सुसे, फिरोज कुवार, आदिल खोत, मुखलिस नाचन, सैफ अतीक नाचन, आह्या खोत, राफिल नाचन, राजिल नाचन, शकुब दिवकर, कासीफ बेलारे, मुंजिर केपी शामिल हैं। इन सबको दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में जांच के लिए ले जाया गया है।

**इंकलाब** (12 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अमृत गिल, रियाजुद्दीन और इजहारुल हक को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने इन आरोपियों को पूछताछ के लिए एक सप्ताह के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जाता है कि अमृत गिल बठिंडा में अमृतपाल सिंह नामक एक फर्जी नाम से रह रहा था। जबकि गाजियाबाद से रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है कि उसे विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में धनराशि भेजी गई थी। जिन खातों से रियाजुद्दीन को धनराशि भेजी गई थी उनके तार आईएसआईएस से जुड़े पाए गए थे। इजहारुल हक को बिहार के चंपारण जिले से गिरफ्तार किया गया है।

## उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने का फैसला

**इंकलाब** (12 दिसंबर) के अनुसार चूड़ियों का शहर और सुहाग की नगरी के नाम से विख्यात नगर फिरोजाबाद का नाम बदला जा रहा है। जिला पंचायत के बाद अब नगर निगम ने भी फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। नगर निगम की कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। अब अंतिम स्वीकृति के लिए इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा गया है। योगी सरकार की मंजूरी के बाद नाम बदला जा सकता है। बैठक में नीरज पटेल ने नाम बदलने के प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद रेहान ने नाम बदलने का विरोध करते हुए कहा कि पहले इस बात को प्रमाणित किया जाना चाहिए कि फिरोजाबाद का नाम कभी चंद्रनगर हुआ करता था। फिरोजाबाद नगर को अकबर के जनरल फिरोज शाह ने बसाया था और वहां पर उसका मकबरा भी मौजूद है।

गौरतलब है कि जुलाई 2021 में जिला पंचायत की पहली बैठक में फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में

पेश किया गया था, जिसे जिला पंचायत ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। अब नगर निगम ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है।

**टिप्पणी:** आजादी के बाद से अब तक देश के 100 से अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। आजादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना और इसका नाम उत्तरांचल पड़ा। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसी तरह से बंगलौर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। पूना का नाम बदलकर पुणे किया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र के अनेक जिलों और स्थानों के नामों को भी बदला गया। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां पर एक दर्जन से भी अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा जा चुका है। वहीं, मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है।

नाम बदलने के अभियान की शुरुआत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने की थी। उनके आंदोलन के कारण अंग्रेज शासकों के नाम पर रखी गई राजधानी दिल्ली की अनेक सड़कों के नाम बदले गए थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के उग्र आंदोलन के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए विदेशी शासकों की चार दर्जन से अधिक प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने इन विदेशी शासकों की प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का निर्णय लिया था। खास बात यह है कि लोहिया ने किसी भी मुगल या विदेशी मूल के मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए सड़कों के नाम बदलने का अभियान नहीं चलाया था। बाद में जनसंघ के नेताओं ने विदेशी मूल के सभी शासकों के नामों पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने के लिए आंदोलन चलाया था। इसके बाद नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने भी विदेशी शासकों के नाम पर रखे गए अनेक मार्गों के नाम बदलने का फैसला किया था। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

# तेलंगाना के भाजपा विधायकों का अकबरुद्दीन ओवैसी से शपथ लेने से इंकार

**औरंगाबाद टाइम्स** (10 दिसंबर) के अनुसार तेलंगाना विधानसभा में भाजपा के नवनिर्वाचित आठ विधायकों ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किए जाने के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए पहले ही दिन विधानसभा का बहिष्कार किया। बहिष्कार का फैसला भाजपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी के निर्देश पर लिया गया था। किशन रेड्डी ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हुए गुप्त समझौते के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस के पास मामूली बहुमत है और उसकी सरकार किसी भी समय गिर सकती है, इसलिए उसने ओवैसी की पार्टी से यह गुप्त समझौता किया है। रेड्डी ने यह दावा किया कि ओवैसी सबसे वरिष्ठ विधायक नहीं हैं। भाजपा ने ओवैसी की प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति के बारे में राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन से भी शिकायत की है। इससे पूर्व तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. सुंदरराजन ने राजभवन में अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई थी। ओवैसी ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने छठी बार चंद्रायनगुट्टा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है। इस समारोह में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पी. श्रीनिवास रेड्डी आदि उपस्थित थे।

गोशामहल से भाजपा के विधायक टी. राजा सिंह ने सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी से शपथ लेने से इंकार कर दिया था। पिछली बार भी उन्होंने एआईएमआईएम के विधायक मुमताज अहमद खान से शपथ लेने से इंकार कर दिया था। राजा सिंह ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं एआईएमआईएम के किसी भी विधायक के सामने विधायक पद की शपथ नहीं लूंगा। राजा सिंह ने कहा कि मैं उस व्यक्ति के सामने शपथ नहीं ले सकता जिसने अतीत में हिंदू विरोधी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि वे इस नियुक्ति के खिलाफ राज्यपाल का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे विरोध प्रकट करेंगे। राजा सिंह ने कांग्रेस को डरपोक करार देते हुए कहा कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की तरह एआईएमआईएम से डरते हैं, इसलिए उन्होंने ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने की अनुमति दी है। जबकि परंपरा के अनुसार विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जोकि अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब स्थाई विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा तभी भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बाद में जब गद्दाम प्रसाद कुमार विधानसभा के स्थाई अध्यक्ष बने तब भाजपा के इन नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।

# डेनमार्क में कुरान के अपमान के खिलाफ कानून पारित

**अवधनामा** (9 दिसंबर) के अनुसार डेनमार्क की संसद ने कुरान सहित अन्य धार्मिक पुस्तकों के अपमान को अपराध घोषित करने के बारे में कानून को पारित कर दिया है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। विदेशी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार डेनमार्क में पिछले कई वर्षों से अतिवादियों द्वारा कुरान एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों के अपमान का सिलसिला जारी है। डेनमार्क में कुरान के अपमान के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट होकर विरोध जता चुके हैं। इसके साथ ही अनेक मुस्लिम देशों ने डेनमार्क के साथ राजनयिकों संबंधों को भी तोड़ लिया था। 179 सदस्यों वाली डेनमार्क की संसद के 94 सांसदों ने इस कानून का समर्थन किया। जबकि 77 ने इसका विरोध किया।

डेनमार्क के न्याय मंत्री ने कहा कि हम डेनमार्क की जनता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए कुछ समूहों द्वारा धार्मिक पुस्तकों की अवमानना का जो सिलसिला जारी था उसे रोकना जरूरी था। अब धार्मिक पुस्तकों, उनके पृष्ठों या फिर उनसे संबंधित सामग्री को सार्वजनिक तौर पर जलाना या उनका अपमान करना गैरकानूनी होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धार्मिक पुस्तकों के अपमान का दोषी पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे दो साल की सजा मिलेगी। गौरतलब है कि इस साल के जुलाई महीने में बगदाद में हजारों कट्टरपंथी मुसलमानों ने डेनमार्क के दूतावास पर हमला करने का प्रयास किया था। इसके बाद इस्लामी देशों में स्थित डेनमार्क के दूतावासों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। डेनमार्क पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस साल 21 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच डेनमार्क में धार्मिक पुस्तकों और झंडों को जलाने या उनका अपमान करने की 483 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इसके बाद डेनमार्क सरकार ने इस संबंध में संसद में कानून लाने की घोषणा की थी, लेकिन अदालतों में इसका विरोध किया गया

था और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ माना गया था।

गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 2017 में डेनमार्क सरकार ने इस संदर्भ में कानून पारित करने का प्रयास किया था, मगर अदालती हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका था। इसके बाद सरकार ने इन घटनाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जनमत जागृत करने का प्रयास किया था, जिसमें उसे सफलता मिली है और यह संसद में हुए मतदान के आकड़ों से स्पष्ट है। जानकार सूत्रों के अनुसार एक अन्य देश स्वीडन भी कुरान के अपमान के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास कर रहा है।

## गाजा में युद्धविराम के प्रयासों की विफलता पर संयुक्त राष्ट्र बेबस

**इंकलाब** (18 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह स्वीकार किया है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्यों में इस मुद्दे पर मतभेद होने के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धविराम के प्रयास विफल रहे हैं।

**उर्दू टाइम्स** (14 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में मानवीय आधार पर युद्धविराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। महासभा के 193 सदस्यों में से भारत सहित 153 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। जबकि अमेरिका और इजरायल सहित कुछ अन्य देशों ने इसका विरोध किया था और 23 देश मतदान में शामिल नहीं हुए थे। युद्धविराम के प्रस्ताव के विरोध में मत देने वाले देशों में अमेरिका और इजरायल के अतिरिक्त चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, ग्वाटेमाला, पैराग्वे, पापुआ न्यू गिनी, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया आदि देश शामिल थे। जबकि अर्जेंटीना और यूक्रेन सहित 23 देशों ने मतदान में

हिस्सा नहीं लिया था। हमास ने युद्धविराम के प्रस्ताव का समर्थन किया था और विश्व के देशों से इस बात का आग्रह किया था कि वे इजरायल पर दबाव डालकर उसे इस युद्धविराम के लिए विवश करें। इस प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई की भी मांग की गई थी और सभी पक्षों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेवारियों को महसूस करते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा एवं गाजा में सहायता को मानवीय आधार पर सुनिश्चित बनाएं। समाचारपत्र के अनुसार यह सिर्फ एक सांकेतिक प्रस्ताव है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के विपरीत संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास अपने प्रस्ताव को लागू करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। इजरायल इस प्रस्ताव पर अमल करे, इसके लिए उस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

**उर्दू टाइम्स** (10 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्धविराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर एक बार फिर से वीटो कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 15 में से 13 सदस्यों ने मतदान किया। जबकि ब्रिटेन ने मतदान में भाग नहीं लिया। वहीं, अमेरिका ने वीटो के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वे वीटो के विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड का कहना था कि प्रस्ताव का प्रारूप असंतुलित है और यह जमीनी सच्चाई के अनुरूप नहीं है। इस तरह के प्रस्ताव पारित करने से समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अमेरिका इस समस्या का स्थाई शांति चाहता है, ताकि इजरायली और फिलिस्तीनी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकें। उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्थिर युद्धविराम की मांग करती है और इससे एक नए युद्ध का बीज बोया जा सकता है। अमेरिकी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि इसे कारगर बनाने के लिए यह बेहतर होता कि अगर इसमें हमास द्वारा इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की जाती, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली मारे गए थे और 240 लोगों को बंधक बनाया गया था। गौरतलब है कि इससे पूर्व अमेरिका ने इस वर्ष के अक्टूबर महीने में ब्राजील द्वारा युद्धविराम के प्रस्ताव को भी वीटो कर दिया था।

**सियासत** (8 दिसंबर) के अनुसार फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने अनुच्छेद 99 के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा शांति के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजरायल के राजनीतिक आतंकवाद की निंदा करे। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद से विधिवत मांग की थी कि वे गाजा पट्टी में तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उन्होंने यह पत्र अनुच्छेद 99 के संदर्भ में लिखा था। 2017 के बाद वर्तमान महासचिव ने पहली बार अपने कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का सहारा लिया। यह अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी प्रतिनिधि को ऐसे किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद में भेजने का अनुरोध कर सकता है जिसके तहत वह यह महसूस करता हो कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे को टालने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

**इंकलाब** (19 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका द्वारा गाजा में युद्धविराम से संबंधित प्रस्ताव को वीटो करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनेक सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने

अमेरिका की इस हरकत को इजरायल के जंगी इरादों का समर्थन बताया है। जबकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इसे अमेरिका का अन्यायपूर्ण रवैया बताया है और यह मांग की है कि स्थाई सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वीटो के अधिकारों पर पुनर्विचार किया जाए। चीन ने इसे अमेरिका की दोहरी नीति बताया है, तो रूस ने इसे अमानवीय कदम बताया है। जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि अमेरिका का यह रूख उनकी समझ से परे है, क्योंकि इससे गाजा में युद्धविराम और शांति स्थापना के मंसूबे धूल में मिल गए हैं।

## पाकिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि

**उर्दू टाइम्स** (13 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के एक महत्त्वपूर्ण सैन्य ठिकाने दरबान में हुए एक आतंकी हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले की पुष्टि पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने की है और कहा है कि सुरक्षाबलों ने इस सैन्य ठिकाने पर आतंकियों के हमले के प्रयास को विफल बना दिया था। इसके बाद आतंकियों ने बारूद से भरे एक वाहन को इस ठिकाने से टकराया, जिसके कारण वहां पर अनेक धमाके हुए और कई लोग मारे गए। रक्षा विभाग के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने सभी छह आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। जबकि 23 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डेरा इस्माइल खान में हुई कई सैन्य कार्रवाई में 27 आतंकी मारे गए।

पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग की सूचना के अनुसार आतंकियों के अड्डों पर सैनिक कार्रवाई की गई और दाराजिंदा क्षेत्र में आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसमें 17 आतंकी मारे गए। वहीं, कुलाची में आतंकियों और सेना के बीच झड़पें हुईं, जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी मारे गए। आतंकियों के अड्डे से काफी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान जारी है।

**औरंगाबाद टाइम्स** (13 दिसंबर) के अनुसार मारे जाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 25 से अधिक बताई जाती है।

**उर्दू टाइम्स** (4 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के सूबा गिलगित-बाल्टिस्तान के नगर चिलास में आतंकियों के एक गिरोह ने एक यात्री बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। इस बात की पुष्टि गिलगित के उपायुक्त आरिफ अहमद ने की है। उन्होंने कहा कि मरने वालों के पांच शवों की पहचान हो गई है, जबकि अन्य लोगों की पहचान बाकी है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कम-से-कम चार लोग मारे गए और कई घायल हो गए।

**हमारा समाज** (4 दिसंबर) के अनुसार पिछले कुछ महीनो में पाकिस्तान में आतंकी

घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। आतंकी सेना और पुलिस को चुन-चुनकर अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तान में 83 आतंकी हमले हुए, जिनमें कम-से-कम 37 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खास बात यह है कि इन हमलों के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बजाय छोटे-छोटे गुटों का हाथ बताया जाता है, जिनमें लश्कर-ए-खुरासान, तहरीक-ए-जिहाद और एक नया आतंकी संगठन जिसका नेता हाफिज गुलबहादुर शामिल हैं। 26 नवंबर 2023 को इस नए संगठन ने बन्नू में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें कम-से-कम सात पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। बताया जाता है कि हमलावरों का संबंध अफगानिस्तान से था।

**उर्दू टाइम्स** (8 दिसंबर) ने पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस न्यूज के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा खून की होली खेलने के लिए अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, जमात-उल-अहरार, हिज्ब-उत-तहरीर, जुंदल्लाह, आईएमयू और बलूच विद्रोही बताए जाते हैं। पाकिस्तान सरकार ने यह आरोप लगाया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ये आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दो सालों में पाकिस्तान में जो आतंकी मारे गए हैं, उनका संबंध अफगानिस्तान से था। सरकारी सूत्रों के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 2020 में 49, 2021 में 198 और 2022 में 237 हमलों में हिस्सा लिया। इस साल इस आतंकी संगठन ने 317 हमले किए जिनमें 389 पाकिस्तानी मारे गए।

## बांग्लादेश के विपक्षी दलों द्वारा चुनाव का बहिष्कार

**इंकलाब** (7 दिसंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी और अन्य विपक्षी दलों के बाद बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी देश में होने वाले आम चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है। पार्टी के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वे किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, इसलिए वे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि शेख हसीना ने पिछले दो चुनावों में भी धांधली करके सफलता प्राप्त की थी और अक्टूबर से लेकर अब तक उनकी पार्टी के 18 हजार से अधिक नेता और समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी और अन्य पार्टियां बांग्लादेश

में अगले महीने के 7 जनवरी से होने वाले चुनावों के बहिष्कार की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं।

**इंकलाब** (9 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दावा किया है कि पिछले दो सप्ताह में जेलों में बंद उनके पांच प्रमुख नेताओं की हत्या शेख हसीना के इशारे पर की जा चुकी है। इन हत्याओं के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किए गए हैं। पिछले पांच सप्ताह में सरकारी कार्रवाई में उनकी पार्टी के 20 हजार से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, सरकार ने विपक्ष के इस दावे का खंडन किया है, मगर उसने यह नहीं बताया कि पुलिस ने अब तक कितने विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपनी हिरासत में लिया है। राष्ट्रव्यापी बंद के सिलसिले में अब तक एक दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी और दो दर्जन नागरिक मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक वाहनों को इन प्रदर्शनों में जलाया गया है। दूसरी विपक्षी पार्टी जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि पिछले दो सप्ताह में उसके 20 समर्थकों की सरकारी इशारे पर हत्या की जा चुकी है।

## फ्रांस के सबसे बड़े इस्लामी स्कूल का सरकारी अनुदान बंद

**रोजनामा सहारा** (12 दिसंबर) के अनुसार फ्रांस की सरकार ने देश के सबसे बड़े इस्लामी स्कूल का सरकारी अनुदान बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि इस स्कूल का पाठ्यक्रम फ्रांस की संस्कृति के अनुरूप नहीं है और इससे उग्रवाद की भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार यह स्कूल 20 साल पहले उत्तरी फ्रांस के नगर लिली में स्थापित किया गया था और इसे फ्रांस का सबसे बड़ा इस्लामी स्कूल माना जाता है। फ्रांस की सरकार ने यह फैसला एक उच्चस्तरीय जांच आयोग की सिफारिश के बाद किया है, जिसने इस स्कूल को अन्य स्रोतों से मिलने वाली गैर-सरकारी सहायता और वहां पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण किया था। फ्रांसीसी समाचारपत्र के अनुसार जांच आयोग ने स्कूल को गैर-सरकारी स्रोतों से मिलने वाली सहायता और पाठ्यक्रम की इस्लामी शिक्षा को फ्रांस की लोकतांत्रिक और सेक्युलर परंपरा के विपरीत माना है और कहा है कि इस पाठ्यक्रम में सिर्फ इस्लाम की ही शिक्षा दी जाती है। जबकि अन्य धर्मों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है, जोकि फ्रांस की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इस फैसले के खिलाफ स्कूल प्रबंधकों ने अदालत में अपील करने का फैसला किया है। इस स्कूल में 800 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस स्कूल को विभिन्न इस्लामी देशों से भारी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। उसके बाद यह स्कूल विवादों में घिर गया था। जांच आयोग को इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि इस स्कूल के पाठ्यक्रम में इस्लाम, कुरान एवं पैगंबर की तौहीन करने वालों के कत्ल करने को जायज ठहराया जाता है और इसमें पृथकतावाद की भी शिक्षा दी जाती है।

# रूस द्वारा अरब जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास

अमेरिका और चीन के बाद अब रूस ने भी अरब जगत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं।

**इत्तेमाद** (8 दिसंबर) के अनुसार हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का अचानक दौरा किया। यूक्रेन के युद्ध के बाद यह तीसरा देश है, जिसका रूसी राष्ट्रपति ने दौरा किया है। इससे पहले वे ईरान और चीन का भी दौरा कर चुके हैं। उनका लक्ष्य मध्य पूर्व में रूस का प्रभाव बढ़ाने का है। रूस की सरकारी मीडिया के अनुसार रूसी राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इजरायल-हमास युद्ध और तेल के कारोबार के बारे में अरब देशों का दौरा कर रहे हैं। रूस ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में शांति के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत के महत्व पर जोर दिया है। खास बात यह है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के सिलसिले में अमेरिकी लॉबी रूस को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में खींचने का प्रयास कर रही है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन और सितंबर में भारत में होने वाले जी-20 सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था। संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत में रूस का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी है। रूस के सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच का व्यापार नौ अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच ऑयल और गैस के क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित अनेक योजनाओं को शुरू करने पर भी बातचीत चल रही है।

इससे पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र का अंतिम दौरा जुलाई 2022 में किया था। तब उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से भी बातचीत की थी। हाल ही में उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मास्को में मुलाकात की है। रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा उस समय हो रहा है जब तेल निर्यात करने वाले देशों और ओपेक देशों की ओर से तेल के उत्पादन में कमी करने के फैसले के बावजूद कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट आई है। गौरतलब है कि ओपेक के सदस्य देश दुनिया के 40 प्रतिशत पेट्रोल का

उत्पादन करते हैं। अमेरिका का प्रयास विश्व में रूस को अलग-थलग करने का था, जो विफल रहा है। रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ओपेक के सदस्य हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के साथ नजदीकी संबंधों के बावजूद रूस को अलग-थलग करने के अमेरिकी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, चीन के प्रयास से ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों के नए युग की जो शुरुआत हुई है, वह अंतरराष्ट्रीय मैदान में अमेरिकी प्रभाव के गिरावट का संकेत है।

**उर्दू टाइम्स** (13 दिसंबर) के अनुसार रूसी विदेश मंत्रालय ने यह संकेत दिया है कि रूस और ईरान के बीच एक नए समझौते पर तेजी से काम हो रहा है। इस समझौते के बारे में अधिक जानकारी देने से रूस ने इंकार कर दिया है। मास्को और तेहरान के बीच हाल ही में राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य रिश्तों की नई शुरुआत से अमेरिका को परेशानी हो रही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने यह संकेत जरूर दिया है कि इस महत्त्वपूर्ण समझौते को करने के बारे में ठोस कदम उठाने पर रूस और ईरान के विदेश मंत्रालयों के बीच सहमति प्रकट की गई है। रूसी राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से पांच घंटे तक मुलाकात की है। ईरान और अमेरिका की शत्रुता जगजाहिर है और ईरान यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को सहयोग कर सकता है।

हाल ही में रूस ने ईरानी ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल किया है। व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है कि ईरान और रूस बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में आपस में सहयोग कर रहे हैं। ईरान इजरायल के दुश्मन हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके ईरान के साथ रूस के बढ़ते हुए खतरनाक सहयोग पर नाराजगी व्यक्त

की है। ईरानी मीडिया के अनुसार रूस के साथ ईरान का सैन्य सहयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

**उर्दू टाइम्स** (8 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि फिलिस्तीन विवाद का स्थाई समाधान तभी हो सकता है, जब फिलिस्तीन के एक अलग राज्य के दर्जे को स्वीकार किया जाए। इसके बिना स्थिर शांति का कोई मार्ग नजर नहीं आता है। दोनों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि सऊदी अरब और रूस ने अंतरराष्ट्रीय शांति को बरकरार रखने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमति प्रकट की है और गाजा में हो रही मानवीय तबाही पर गहरी चिंता प्रकट की है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की सैनिक कार्रवाईयों को तुरंत रोकने पर जोर दिया गया है। संयुक्त बयान के अनुसार 1967 से पूर्व की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और पूर्वी यरुशलम को इसकी राजधानी घोषित करने से इस क्षेत्र में स्थाई शांति का दरवाजा खुल सकता है। दोनों देशों ने विश्व से अपील की है कि वह स्वतंत्र और स्वशासी फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने के प्रयासों को तेज करें और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों को रोकने के लिए उस पर दबाव डालें। दोनों देशों ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के स्थाई युद्धविराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

# सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले

**उर्दू टाइम्स** (10 दिसंबर) के अनुसार ईरान समर्थक दो मिलिशिया संगठनों हमास और हिजबुल्लाह ने सीरिया और इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबर्दस्त हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में इन दोनों संगठनों ने 50 बार कम-से-कम दस अमेरिकी ठिकानों को मिसाइल और रॉकेटों का निशाना बनाया है। इसके जवाब में अमेरिकी विमानों ने सीरिया और इराक में स्थित हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 40 बार हमले किए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाया है।

**हमारा समाज** (14 दिसंबर) के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि हम अपनी भूमि पर अमेरिका का कोई हमला स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने इस संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री से भी विशेष रूप से बातचीत की है और कहा है कि इससे हमास और इजरायल का युद्ध मध्य पूर्व के अन्य देशों तक भी फैल सकता है। गौरतलब है कि इस महीने के प्रारंभ में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इराक की भूमि पर ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए थे और उनके अनेक लड़ाकों को मार गिराया था। पेंटागन के अनुसार क्योंकि ईरान समर्थक इन मिलिशिया संगठनों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे, इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए अमेरिका को इनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी है। अमेरिका ने दावा किया है कि पिछले दो महीनों में ईरान समर्थक इन संगठनों ने 34 बार इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी सैन्य विमानों ने ईरान समर्थक सैन्य संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। बताया जाता है कि इस संगठन का संबंध इराक में सक्रिय हिजबुल्लाह से है। अमेरिका का दावा है कि आईएसआईएस के खिलाफ इराकी सेना की कार्रवाई में सहयोग देने के लिए ढ़ाई हजार अमेरिकी सैनिक इस समय इराक में है। अमेरिका ने इराक से अनुरोध किया है कि इराक में रहने वाले अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए और उन पर ईरान समर्थकों के हमलों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। सीरिया में भी कुर्द विद्रोहियों और ईरान समर्थक मिलिशिया संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी सैनिक अड्डों पर 900 से अधिक अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। इनकी संख्या में और अधिक वृद्धि किए जाने की भी संभावना है।

# नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की जेल में भूख हड़ताल

**मुंबई उर्दू न्यूज** (11 दिसंबर) के अनुसार ईरान में हिजाब को जबरन लागू करने और वहां के न्यायालय द्वारा निर्दोष लोगों को फांसी दिए जाने का विरोध करने वाली ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने तेहरान जेल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मोहम्मदी को पिछले साल ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ईरान की महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के कारण यह पुरस्कार दिया गया था। नार्वे की राजधानी ओस्लो में एक प्रेस कांफ्रेंस में नरगिस मोहम्मदी के भाई हामिद रजा मोहम्मदी और उनके पति ताघी रहमानी ने कहा कि नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में अल्पसंख्यक बहाई संप्रदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए जेल में भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान में बहाई संप्रदाय के सैकड़ों नेता अवैध रूप से जेलों में बंद हैं और उन्हें सरकार उत्पीड़न का शिकार बना रही है। बहाई संप्रदाय ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। कट्टरपंथी शिया उनकी अलग धार्मिक पहचान और आस्था को जबरन खत्म करके उन्हें शिया संप्रदाय का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ईरान में बहाई संप्रदाय के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उन्हें झूठे आरोपों में फांसी पर लटकाया जा रहा है।

वहीं, 51 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी पेशे से वकील हैं। पिछले साल सितंबर महीने में तेहरान में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हत्या के बाद जो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, उसका सार्वजनिक रूप से समर्थन करने पर ईरान सरकार ने नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद कर दिया था। इससे पूर्व भी मोहम्मदी को ईरान सरकार 13 बार गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें 31 साल जेल में बिताने की सजा दी जा चुकी है। इसके साथ ही उन्हें इस्लामी अदालतों ने 154 कोड़े मारने की भी सजा दी थी। उन्हें ईरानी अदालतों द्वारा पांच बार सजा दी जा चुकी है। आखिरी बार दो साल पहले मोहम्मदी को ईरानी अदालत ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह जेल में बंद हैं। उनके बच्चे और पति फ्रांस में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

# सऊदी अरब द्वारा भारतीयों के लिए उमरा को आसान बनाने की घोषणा

**इंकलाब** (6 दिसंबर) के अनुसार भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के मंत्री तौफिक बिन फौजान ने कहा है कि सऊदी सरकार ने भारतीयों के लिए उमरा अदा करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की घोषणा की है। अब भारतीय नागरिक केवल दो दिन के अंदर ही उमरा का वीजा प्राप्त कर सकेंगे। सऊदी सरकार ने जो आधुनिक तकनीक अपनाई है उसके कारण उमरा और अन्य सरकारी मामलों में वीजा को आसान बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत से उमरा के लिए सऊदी अरब जाने वालों की संख्या 12 लाख से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए उमरा को आसान बनाने हेतु सऊदी सरकार ने दोनों देशों के बीच सस्ती विमान सेवा चलाने का भी प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन से भी बातचीत की है। सऊदी अरब ने भारत में तीन नए वीजा सेंटर खोलने का भी फैसला किया है।

पश्चिमी देशों की यात्रा करने वाले भारतीय 96 घंटे के लिए सऊदी अरब में अस्थाई प्रवास हेतु वीजा प्राप्त कर सकते हैं। सऊदी मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि भारतीयों को हज यात्रा करने का अधिक-से-अधिक अवसर दिया जाए और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएं। भारत सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि महिलाओं और विकलांग हाजियों को हज की यात्रा करने की विशेष सुविधा मिले। भारत सरकार भी 2024 के लिए नई हज नीति की घोषणा कर चुकी है और

हज के लिए जाने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सऊदी मंत्री ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत और सऊदी अरब के बीच नए रिश्तों की शुरुआत हुई है।

**रोजनामा सहारा** (7 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए सभी नगरों और ऐतिहासिक स्थानों के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी तक उमरा के लिए जाने वाले लोगों को मक्का और मदीना के अतिरिक्त किसी अन्य जगह जाने की अनुमति नहीं होती थी, मगर सऊदी अरब की नई पर्यटन नीति के अनुसार वे अब सऊदी अरब के किसी भी स्थान की यात्रा कर सकेंगे। सऊदी सरकार ने निजी टूर ऑपरेटरों को भी विशेष सुविधाएं देने की घोषणा की है, ताकि वे हज और उमरा करने के इच्छुक भारतीयों को विशेष कार्यक्रम के तहत सुविधाएं दे सकें। भारत से मदीना के लिए सीधी हवाई सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं और विमानों की संख्या में वृद्धि की जा रही हैं।

# सऊदी अरब में पूंजी निवेश करने वाली कंपनियों को करों में 30 वर्ष की छूट

**रोजनामा सहारा** (8 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि राजधानी रियाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अगले तीस सालों तक निरंतर करों में छूट दी जाएगी। टैक्स रिलीफ पैकेज के तहत कॉर्पोरेट और विदहोल्डिंग टैक्स की दर इन कंपनियों के लिए शून्य कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां सऊदी नागरिकों को नौकरियां और रोजगार देंगी उन्हें इसके बदले में असीमित वर्क वीजा की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इन कंपनियों के अधिकारियों के परिवारजनों को भी वर्क परमिट की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

गौरतलब है कि फरवरी 2021 में सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को इस बात का आमंत्रण दिया था कि वे सऊदी अरब में पूंजी निवेश करें, ताकि सऊदी नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और देश आर्थिक रूप से विकसित हो सके। सरकार का लक्ष्य यह है कि सऊदी अरब की विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की नई नीति के कारण सऊदी अरब की राजधानी रियाद मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके। इस नीति के कारण 200 से अधिक विदेशी कंपनियों को राजधानी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। सऊदी सरकार को आशा है कि इन सुविधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की सऊदी अरब में पूंजी निवेश में रुचि बढ़ेगी और सऊदी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

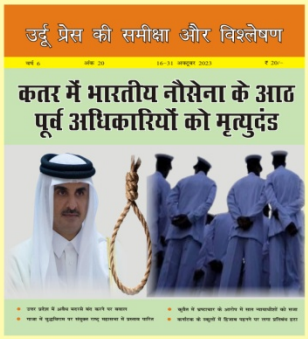

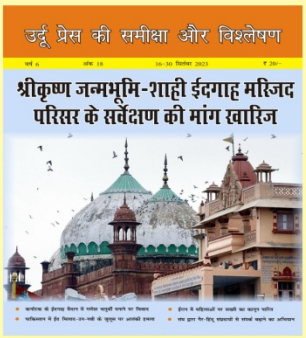

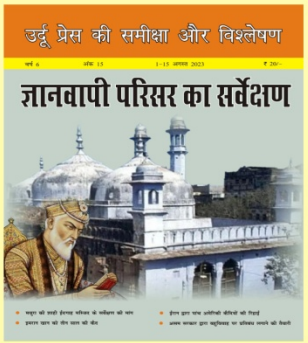

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in